डॉ. मनोज सोनी

डॉ. मनोज सोनी वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं; इस कार्यभार से पहले, डॉ. सोनी ने संघ लोक सेवा आयोग में 28 जून, 2017 से 15 मई, 2023 तक सदस्य के रूप कार्य किया।

डॉ. सोनी ने तीन बार कुलपति के रूप में कार्य किया ; इसमें डॉ. बाबा साहेब आम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (बी ए ओ यू) के कुलपति के रूप में 1 अगस्त, 2009 से लेकर 31 जुलाई, 2015 तक लगातार दो कार्यकाल और महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा (दि एम.एस.यू. ऑफ बड़ौदा) के कुलपति के रूप में अप्रैल, 2005 से अप्रैल, 2008 तक का एक कार्यकाल शामिल है। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में पदभार ग्रहण करते समय, डॉ. सोनी भारत के अभी तक के सबसे युवा कुलपति थे ।

आन्तर-राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में विशेषज्ञता के साथ राजनीति विज्ञान के एक स्कॉलर के रूप में डॉ. सोनी ने दो विश्वविद्यालयों के कुलपति के पद की सेवा अवधि को छोड़कर, सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) वल्लभ विद्यानगर में 1991 से 2016 के बीच आन्तर-राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अध्यापन कार्य किया। डॉ. सोनी ने “पोस्ट-कोल्ड वार इन्टरनेशनल सिस्टेमिक ट्रांजिशन एण्ड इण्डो-यू.एस. रिलेशन्स” विषय पर डॉक्ट्रेट किया है। यह 1992 और 1995 के दौरान सबसे पहला और अपनी तरह का विशेष अध्ययन था। इसके द्वारा संकल्पनात्मक ढ़ांचे के माध्यम से शीतयुद्ध के बाद व्यवस्थित ट्रांजिशन को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, जिसमें संभावित आंकलन की संभावनाएं हैं। यह कार्य बाद में 1998 में यू.के. में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रकाशक अश्गेट पब्लिशिंग लि., न्यू हैम्पशायर के द्वारा “अन्डरस्टैडिंग द ग्लोबल पॉलीटिकल अर्थक्वेक” नामक शीर्षक के अंतर्गत एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ।

डॉ. सोनी को बहुत से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2013 में, डॉ. सोनी को आई टी साक्षरता के साथ समाज के वंचित वर्ग को सशक्त बनाने में अनुकरणीय नेतृत्व के लिए बेटन रूज, लुसियाना, यू.एस.ए. के मेयर प्रेसीडेंट द्वारा "ऑनरेरी मेयर-प्रेसीडेंट ऑफ द सिटी ऑफ बेटन रूज" सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2015 में, डॉ. सोनी को चार्टेड इन्स्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउन्टेंट्स लंदन, यू.के. द्वारा दूरस्थ शिक्षा नेतृत्व के लिए वर्ल्ड एजुकेशन कांग्रेस ग्लोबल अवार्ड दिया गया।

डॉ. सोनी ने उच्चतर शिक्षा और लोक प्रशासन की अनेक शिक्षा संस्थाओं के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। वे गुजरात विधान सभा के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय, जो गुजरात में गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं के फीस ढ़ांचे को विनियमित करता है, के भी सदस्य रहे हैं।